भारतीय साबुन एवं प्रसाधन निर्माता संगठन

बनाम

ओजैर हुसैन एवं अन्य

सिविल अपील सं. 5645/2003

मार्च 7, 2013

(जी.एल. सिंघवी एवं सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय न्यायाधिपतिगण)

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940- औषधि- सामग्री- प्रकटीकरण- शाकाहारी/मांसाहारी- उच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दवा निर्माताओं को 'मांसाहारी'/'शाकाहारी' मूल के अवयवों की पहचान करने के लिए जीवन रक्षक दवाओं के अलावा अन्य दवाओं के पैकेजों में एक विशेष प्रतीक प्रदर्शित करने का निर्देश देता है- औचित्य- निर्धारित किया: किसी दी गयी परिस्थिति में, किसी रोगी की ऐसी स्थिति हो सकती है कि उसके लिए ऐसी दवा हो सकती है जिसे आमतौर पर जीवन रक्षक दवा के रूप में नहीं माना जाता है, वह जीवन बचाने के लिए आवश्यक हो सकती है- ऐसे मामले में जब दवा जीवन रक्षक दवा बन जाती है, तो रोगी या उसके परिचारक के लिए यह जानना

वांछनीय नहीं हो सकता है दवा के अवयवों की उत्पत्ति अर्थात चाहे 'शाकाहारी' या 'मांसाहारी'- इसके अलावा, व्यक्तिगत मामलों में, केंद्र सरकार को 'शाकाहारी' या 'मांसाहारी' घटक की उत्पत्ति निर्दिष्ट करने में कठिनाई महसूस हो सकती है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन की आदत के आधार पर ऐसे 'शाकाहारी' या 'मांसाहारी' घटक की निश्चित उत्पत्ति जानना चाहता है। औषधि और कॉस्मेटिक नियमों के तहत, केंद्र सरकार को औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से यह निर्णय लेने का अधिकार है कि क्या शाकाहारी या मांसाहारी मूल के अवयवों को दिखाने या एक प्रतीक प्रदान करने के लिए प्रासंगिक नियमों में कोई संशोधन किया जाना है- सलाहकार बोर्ड के साथ उपयोगी परामर्श के बिना, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के लेबल को बदलने के लिए कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है या सुझाव नहीं दिया जा सकता है- पहले के संदर्भ में, सलाहकार बोर्ड ने पहले ही रॉय दे दी थी कि दवाओं की लेबलिंग 'शाकाहारी' या 'मांसाहारी' या 'पशु स्रोतों से' वांछनीय नहीं है- उच्च न्यायालय के पास अन्तर्गत अनुच्छेद 226 कार्यपालिका को एक विशेष तरीके से कानून बनाने के लिए विधायिका द्वारा सौंपी गई शक्ति के अनुसार अधीनस्थ विधान के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करने का निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया था- उसी प्रकार से, यह भी अधिकार नहीं था कि उच्च न्यायालय किसी अंतरिम व्यवस्था का सुझाव देवे जैसा

कि आक्षेपित निर्णय द्वारा दिया गया था- भारत का (2013)4 ऐसेसीआर 676 संविधान, 1950- अनुच्छेद 226 भारत का संविधान, 1950 –अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(2) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता –सूचना प्राप्त करने का अधिकार निर्धारित किया : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार शामिल है- लेकिन इस तरह के अधिकार को अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए बनाए गए कानून के तहत उचित प्रतिबंधों द्वारा सीमित किया जा सकता है।- नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के अधिकार की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य के लिए अनिवार्य है- लेकिन ऐसी जानकारी दूसरों के मौलिक अधिकार को प्रभावित किए बिना, उपलब्ध और संभव सीमा तक दी जा सकती है।

प्रत्यथी ने रिट याचिका (पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन) दायर की, जिसमें सौंदर्य प्रसाधनों, दवाओं और खाद्य पदार्थों के उपभोक्ता के ऐसे उत्पाद के अवयवों के पूर्ण प्रकटीकरण के अधिकार का दावा किया गया, जिससे इसकी उत्पत्ति (शाकाहारी/मांसाहारी) के बारे में स्पष्ट संकेत मिले। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा माना कि उपभोक्ता को यह जानने का मौलिक अधिकार है कि जीवन रक्षक दवाओं के अलावा अन्य दवाएं मांसाहारी या शाकाहारी मूल की हैं या नहीं और ऐसी दवाओं के लेबलिंग

पर कुछ निश्चित चिह्न प्रदान करने का निर्णय दिया।

तत्कालीन अपीलों में निम्न प्रश्न सम्मिलित थेः-

(1) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माताओं को उनके द्वारा निमिर्त सामग्री पर ''मांसाहारी या शाकाहारी'' मूल की पहचान बाबात प्रतीक चिन्ह लगाने के निर्देश देने का क्षेत्राधिकार है?

(2) क्या दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के पैकेजों में मांसाहारी सामग्री की उत्पति के बारे में कोई पहचान प्रदर्शित करना व्यवहाँरिक और वांछनीय था? और

(3) क्या उच्च न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार को परमादेश जारी करना उचित था कि नियमों में संशोधन कर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर अभिनिर्धारित कियाः-

1.1 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 या उसके तहत बनाए गए नियमों में मांसाहारी या शाकाहारी मूल की सामग्री का उल्लेख या प्रतीक प्रदर्शित करना अनिवार्य नहीं है। निर्माता या अन्य को दवाओं या सौंदर्य प्रसाधनों के लेबल पर 'शाकाहारी' या 'मांसाहारी' का उल्लेख करने

की आवश्यकता नहीं है।केंद्र सरकार को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के तहत औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से 'दवाओं और प्रसाधन सामग्री के लेबल' में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के साथ सार्थक परामर्श के बिना, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के लेबल को बदलने के लिए कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है या सुझाव नहीं दिया जा सकता है।[पैरा16] [695]

1.2 इससे पहले कुछ व्यक्तियों द्वारा 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945' में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया था ताकि दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के लेबल पर "शाकाहारी" और "मांसाहारी" शब्दों का उल्लेख किया जा सके। सार्थक विचार-विमर्श के बाद, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने 8 जुलाई, 1999 को आयोजित अपनी 48 वीं बैठक में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। [पैरा17] [696]

2 संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत एक नागरिक को अभिव्यक्ति और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार अनुच्छेद में शामिल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से प्राप्त होता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। इस तरह के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए बनाए गए कानून के तहत उचित प्रतिबंधों द्वारा सीमित

किया जा सकता है। नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के अधिकार की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य के लिए अनिवार्य है लेकिन ऐसी जानकारी दूसरों के मौलिक अधिकार को प्रभावित किए बिना उस सीमा तक दी जा सकती है, जहां तक यह उपलब्ध और संभव है।[पैरा18,19] [698,699]

यू.पी. राज्य बनाम राज नारॉयण और अन्य (1975) 4 एससीसी 428: 1975(3) ऐसेसीआर 333; सूचना और प्रसारण भारत सरकार और अन्य बनाम बंगाल और अन्य क्रिकेटर संघ (1995) 2 एससीसी 161: 1995 (1 ऐसेसीआर 1036 और पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सीबीआइर्/ऐसेपीई) (1998) 4 एससीसी 626: 1998 (2) ऐसेसीआर 870 संदर्भित।

3.1 दी गई परिस्थितियों में किसी रोगी की स्थिति ऐसी हो सकती है कि एक दवा जिसे आमतौर पर जीवन रक्षक दवा के रूप में नहीं माना जाता है, वह जीवन बचाने के लिए आवश्यक हो सकती है। ऐसे मामले में जब दवा जीवन रक्षक दवा बन जाती है, तो रोगी या उसके परिचारक के लिए दवा के अवयवों की उत्पत्ति यानी 'शाकाहारी' या 'मांसाहारी' जानना वांछनीय नहीं हो सकता है। यदि जीवन बचाने या किसी बीमारी को खत्म करने के लिए आवश्यक हो तो ऐसा विकल्प रोगी या उसके परिचारक पर

नहीं छोड़ा जा सकता है।[पैरा21][699]

3.2 यदि किसी दवा या कॉस्मेटिक के अवयवों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी का दावा करना सही है, तो एक शाकाहारी भी अपने भोजन की आदत के आधार पर शाकाहारी घटक की उत्पत्ति के बारे में जानकारी का दावा कर सकता है। भारत में खान-पान की आदत व्यक्ति-व्यक्ति और जगह-जगह के अनुसार अलग-अलग होती है। ऐसी आदत बनाने में धर्म भी अहम भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत मामले में, केंद्र सरकार को 'शाकाहारी' या 'मांसाहारी' घटक की उत्पत्ति निर्दिष्ट करने में कठिनाई महसूस हो सकती है, यदि कोई व्यक्ति उसकी भोजन की आदत का आधार ऐसे 'शाकाहारी' या 'मांसाहारी' घटक की निश्चित उत्पत्ति जानना चाहता है। [पैरा22,23] [699,700]

4.1 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स' में उक्त नियमों में संशोधन के संबंध में ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के किसी भी सुझाव पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इससे पहले एक संदर्भ में औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड पहले ही रॉय दे चुका है कि दवाओं पर 'शाकाहारी' या 'मांसाहारी' या 'पशु स्रोतों से प्राप्त' का लेबल लगाना वांछनीय नहीं है और इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। [पैरा24] [700]

4.2 प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि "जहां क्षेत्र खाली रह गया है, वहाँं भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ऐसा निर्देश", यह न्यायालय जारी कर सकता है, लेकिन इस तरह के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि वह क्षेत्र खाली रह गया है क्योंकि ड्रग्स और कॉस्मेटिक नियमों के तहत यह केंद्र सरकार है जिसको ड्रग तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से यह निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है कि संबंधित नियमों में शाकाहारी या मांसाहारी मूल की सामग्री दिखाने या कोई प्रतीक प्रदान करने के लिए कोई संशोधन किया जाना है या नहीं। [पैरा 28] [702,703]

ए.के. रॉय बनाम भारत संघ और अन्य (1982)1 ऐसे.सी.सी 271: 1982 (2) ऐसेसीआर 272; उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बनाम भारत संघ और एक अन्य (1989) 4 एससीसी 187:1989 (3) ऐसेसीआर 488 बाल राम बाली और एक अन्य बनाम संघ भारत (2007) 6 एससीसी. 805 और भारत संघ बनाम संघ लोकतांत्रिक सुधारों के लिए और एक अन्य (2002) 5 एससीसी 294:2002 (3) ऐसेसीआर 696 संदर्भित।

5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास विधानमंडल द्वारा कानून बनाने के लिए सौंपी गई शक्ति के अनुसार

अधीनस्थ विधान के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करने के लिए कार्यपालिका को निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। एक विशेष तरीके से, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। इसी कारण से, उच्च न्यायालय किसी भी अंतरिम व्यवस्था का सुझाव देने के लिए भी स्वतंत्र नहीं था, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में दिया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई रिट याचिका इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए सुनवाई योग्य नहीं है, उच्च न्यायालय को रिट याचिका को तुरंत खारिज कर देना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश और निर्देश रद्द किये जाते हैं [पैरा 29,30] [703]

संदर्भित न्याय निर्णय

1975(3) ऐसेसीआर 333 संदर्भित किया गया	पैरा 18
1995(1)ऐसेसीआर 1036 संदर्भित किया गया	पैरा 18
1998(2)ऐसेसीआर 870 संदर्भित किया गया	पैरा 18
1982(2)ऐसेसीआर 272 संदर्भित किया गया	पैरा 25
1989(3)ऐसेसीआर 488 संदर्भित किया गया	पैरा 26
(2007)6 एससीसी 805 संदर्भित किया गया	पैरा 27

2002(3)ऐसेसीआर696 संदर्भित किया गया पैरा 28

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील न. 5644/2003

उच्च न्यायालय दिल्ली, नई दिल्ली के सिविल रिट याचिका संख्या 837/2001 एवं सिविल अपील संख्या 5645/2003 में निर्णय और आदेश दिनांकित 13-11-2022 से।

टी.ऐसे. दोआबिया, राज. पंजवानी, अमर दवे, राधिका गौतम, गौरव गोयल ई.सी. अग्रवाल के लिए और.के.राठौड, सुनीता शर्मा, शलिंदर सैनी, डी.ऐसे. माहरा, आदित्य श्यामलाल, विजय पंजवानी, बी.वी. बलराम दास उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

1. ये अपीलें अपीलकर्ताओं द्वारा एक जनहित याचिका (सिविल रिट याचिका संख्या 837/2001) में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 13 नवंबर, 2002 के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा था कि उपभोक्ता को यह जानने का मौलिक अधिकार है कि मानव उपभोग के लिए उपलब्ध खाद्य उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन और दवाएं मांसाहारी या शाकाहारी मूल की हैं या नहीं और उन्हें

निम्नानुसार क्रमबद्ध किया गया है:

(2013)4 ऐसेसीआर 680

"जहां तक सौदर्य प्रसाधनों का सवाल है, उनके अवयवों के प्रकटीकरण के उद्देश्य से उन्हें खाद्य पदार्थों/भोजन के पैकेजों के समान माना जाना चाहिए।"

जब तक अपेक्षित संशोधन नहीं हो जाते, हम निम्नानुसार निर्देश देते हैं:-

(1) जहां किसी कॉस्मेटिक या जीवन रक्षक दवा के अलावा अन्य दवा, जैसा भी मामला हो, में मांसाहारी मूल के तत्व शामिल हैं, पैकेज पर मुख्य डिस्प्ले पैनल पर दवा या कॉस्मेटिक का नाम या ब्रांड के निकट नाम लाल रंग में निम्नलिखित प्रतीक वाला लेबल होना चाहिए,

(2) जहां किसी कॉस्मेटिक या जीवन रक्षक दवा के अलावा अन्य दवा, जैसा भी मामला हो, में पूरी तरह से शाकाहारी मूल की सामग्री शामिल है, पैकेज पर मुख्य डिस्प्ले पैनल पर नाम के ठीक करीब दवा या कॉस्मेटिक का ब्रांड नाम के पास हरे रंग में निम्नलिखित प्रतीक अंकित होना चाहिए

(3) जहां किसी कॉस्मेटिक या जीवन रक्षक दवा के अलावा अन्य

दवा में मांसाहारी मूल के शाकाहारी तत्व होते हैं, तो उत्पाद की उत्पत्ति की प्रकृति को इंगित करते हुए पैकेज पर लिखित रूप में एक घोषणा की जाएगी।

(4) भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक/औषधि महानियंत्रक, दो महीने की अवधि के भीतर जीवन रक्षक दवाओं की एक सूची जारी करेंगे।

2. प्रत्यर्थी द्वारा जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें सौंदर्य प्रसाधनों, दवाओं और खाद्य पदार्थों के उपभोक्ता के अधिकार का दावा करते हुए ऐसे उत्पाद की सामग्री के पूर्ण प्रकटीकरण का दावा किया गया था, जिससे इसकी उत्पत्ति (शाकाहारी / मांसाहारी) के बारे में स्पष्ट संकेत मिलता है।

उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए), अनुच्छेद 21 और 25 के तहत प्रत्याभूत संवैधानिक अधिकारों का जिक्र करते हुए निर्धारित किया:

> "..... हमें ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को अपने विश्वासों और विचारों का सार्थक तरीके से अभ्यास करने में सक्षम बनाने के लिए, उसके लिए प्रासंगिक जानकारी प्राप्त

करना आवश्यक है, अन्यथा वह अपने विश्वासों और विचारों के साथ अनुरूप कार्य नही कर सकेगा। यदि एक शाकाहारी उपभोक्ता सौंदर्य प्रसाधनों, दवाओं या खाद्य उत्पादों जिसे वह खरीदना चाहता है, की सामग्री को नहीं जानता है तो उसके लिए शाकाहार का अभ्यास करना मुश्किल होगा। उपरोक्त संदर्भ में, अनुच्छेद 19(1)(ए) में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दो व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है- (1) यह उपभोक्ता को उत्पादों की संरचना के बारे में सच्चाई का पता लगाने में मदद कर सकती है, चाहे वे पक्षियों सहित जानवरों और ताज़ा पानी या समुद्री जानवर या अंडे, से बने हों और (2) यह उसे शाकाहार में उसके विश्वास या रॉय को पूरा करने के लिए रोक सकता है।"

".....इस मामले को देखते हुए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को अपनी रॉय का पालन करने और उस पर कायम रहने की स्वतंत्रता देता है, और इसको अपनाने के लिए उसे सौंदर्य प्रसाधनों, औषधियों और खाद्य उत्पादों की सामग्री या घटकों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और साथ ही यह

अधिकार भी है।"

"……..उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा विचार है कि यह जानना उपभोक्ताओं का मौलिक अधिकार है कि खाद्य उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन और दवाएं मांसाहारी या शाकाहारी मूल की हैं, अन्यथा यह उनके संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए), 21 और 25 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।। तदनुसार, हम मुख्य प्रश्न का उत्तर हाँ में देते हैं। चूंकि उपभोक्ताओं को सौंदर्य प्रसाधनों, दवाओं और खाद्य पदार्थों की सामग्री के पूर्ण प्रकटीकरण का संवैधानिक रूप से प्रत्याभूत अधिकार है, इसलिए शेष प्रश्नों (ii) और (iii) के उत्तर सकारात्मक रूप से दिए जाने आवश्यक हैं। तदनुसार, हम प्रश्न (ii) और (iii) का उत्तर भी सकारात्मक में देते हैं……."।

"……..जहा तक खाद्य पदार्थो का प्रशन है खाना शाकाहारी है या मांसाहारी. बाबत खाद्य पदार्थ पर उपयोक्ता की सूचनार्थ आवश्यक सूचना की व्यवस्था की गयी है। दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों का संबंध है, संबंधित क़ानूनों में आवश्यक संशोधन नहीं किए गए हैं। जहां तक जीवन रक्षक दवा का सवाल है, एक दृष्टिकोण यह है कि यह जानकारी: चाहे यह पूरी तरह से

या आंशिक रूप से किसी जानवर से प्राप्त या निर्मित की गई हो, का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह बीमारी से लड़ने और जीवन बचाने के लिए है। दूसरे शब्दों में, एक मरीज, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जो जीवन रक्षक दवा न दिए जाने पर घातक हो सकती है, को उसके हित में यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि दवा में किसी जानवर का अंश है या नहीं। यह जीवन के संरक्षण के लिए सहायक है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है। इसका मतलब यह भी है कि जीवन रक्षक दवा देने के मामले में उसके पास कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। कई मामलों में मरीज़ बेहोश होते हैं और उन्हें जीवन रक्षक दवाएं देनी पड़ती हैं। किसी भी स्थिति में वे दवाओं के चयन के मामले में सोच-समझकर निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए, इन परिस्थितियों में, जीवन रक्षक दवाओं के मामले में उपरोक्त दृष्टिकोण लागू होना चाहिए। यह सीमित अपवाद केवल जीवन रक्षक दवाओं पर लागू होगा। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि सभी दवाएं जीवन रक्षक दवाओं के रूप में माने जाने के योग्य नहीं हैं। जो दवाएं जीवन रक्षक दवाएं नहीं हैं, उन्हें खाद्य उत्पादों के समकक्ष रखा जाना चाहिए और यह बताना चाहिए कि वे पूरी तरह से या आंशिक रूप से जानवरों से बनी हैं या नहीं,

"जहां तक सौदर्य प्रसाधनों का सवाल है, उनके अवयवों के

प्रकटीकरण के उद्देश्य से उन्हें खाद्य पदार्थों/भोजन के पैकेजों के समान माना जाना चाहिए।"

3. जहां तक दवाओं का संबंध है, अपीलकर्ता भारत संघ को गंभीर विरोधाभास का डर है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, यह अंतर करना संभव नहीं है कि कौन सी दवा 'जीवन रक्षक दवा' है या अन्यथा है। रोगी की दी गई परिस्थिति और स्थिति में, एक दवा जिसे आमतौर पर 'जीवन रक्षक दवा' के रूप में नहीं माना जा सकता है, उसे जीवन रक्षक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी अन्य मामले में यह सामान्य हो सकता है। इस प्रकार, दवाओं को जीवन रक्षक या अन्यथा के रूप में सीमांकित करना संभव नहीं है। इसलिए, भारत संघ द्वारा जीवन रक्षक दवाओं की सूची तैयार करने की आवश्यकता की सीमा तक, उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश न तो उपयुक्त होगा और न ही उचित, खासकर जब आधुनिक दवा प्रणाली के फार्माकोलॉजी में 'जीवन रक्षक दवा' की कोई परिभाषा नहीं है।

4. आगे यह तर्क दिया गया कि प्रत्येक दवा को बीमारियों को ठीक करने, कम करने या रोकने के जीवन को बचाने या बढ़ाने में उपयोगी माना जाता है। यह देखते हुए कि हर बीमारी में समय पर इलाज न होने पर जान जाने की संभावना होती है, 'जीवन रक्षक दवा' की पहचान आवश्यकता

पड़ने पर विभिन्न स्थितियों की पहचान पर निर्भर करेगी। 5. इसके अलावा, भारत संघ के विद्वान वकील के अनुसार, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर खतरे का प्रतीक रेड लेबल लगाने के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश अनुचित है, खासकर तब जब एक सौंदर्य प्रसाधन अनुभागीय समिति ने कुछ कॉस्मेटिक उत्पादों पर लेबल लगाने के लिए रंग 'ब्राउन' के उपयोग की सिफारिश की थी। उन्होंने औषधि और प्रसाधन समग्री अधिनियम की धारा 5 के तहत गठित 'औषधि तकीनीकी सलाहकार बोर्ड' द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी भरोसा जताया, जिसमें 'मांसाहारी मूल के घटक' के रूप में कोई पहचान प्रदान नहीं करने का कारण बताया गया था।

6. अपीलकर्ता-इंडियन सोप्स एंड टॉयलेटरीज़ मेकर्स एसोसिएशन (बाद में 'एसोसिएशन' के रूप में संदर्भित) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 'शाकाहारी' या 'गैर शाकाहारी' की सामग्री के रूप में कोई पहचान देना न तो व्यावहाँरिक है और न ही वांछनीय है। इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग का शाकाहारी या मांसाहारी मूल सामग्री से कोई लेना- देना नहीं है; वे 'खाद्य उत्पाद' नहीं हैं और निगलने के लिए नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि मांसाहारी सामग्री की उत्पत्ति की पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि उस मूल स्रोत को जानना बहुत मुश्किल है जिससे ऐसी सामग्री प्राप्त हुई है।

7. एसोसिएशन की ओर से निम्नलिखित तर्क भी दिये गये:

(ए) खाद्य पदार्थों के विपरीत, आमतौर पर कॉस्मेटिक वस्तुएं निगलने योग्य नहीं होती हैं। "शाकाहारी" "मांसाहारी" शब्दों की हर एक शब्दकोश परिभाषा भोजन या खाने की क्रिया से संबंधित है। इसलिए, किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए उपभोक्ताओं द्वारा लाई गई भावनात्मक भावना कॉस्मेटिक वस्तुओं पर लागू नहीं होती है। तर्क, यथा भावनात्मक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक, स्वास्थ्य मूल्य, जिसके लिए पशु और गैर-पशु स्रोतों से आने वाले खाद्य पदार्थों के लिए क्रमशः शाकाहारी और मांसाहारी के संदर्भ में अलग-अलग मापदण्ड की आवश्यकता होती है, कॉस्मेटिक वस्तुओं के लिए निम्न कारणो से लागू नहीं होती है (i) इसके बाहरी अनुप्रयोग के कारण और (ii) कॉस्मेटिक संरचना के बारे में उपभोक्ताओं के बीच लंबे समय से चली आ रही और सामान्य जागरूकता के कारण।

(ख) खाद्य उद्योग के विपरीत, जहां भोजन का प्रसंस्करण प्राथमिक उत्पाद के निकट या प्राथमिक उत्पाद केंद्र से एक कदम दूर होता है और अंतिम खाद्य पदार्थ को उपभोग के लिए पैक करने से पहले कई मध्यवर्ती चरण शामिल नहीं होते हैं, कॉस्मेटिक उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के चरण से बहुत दूर है। सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण काफी बड़ी संख्या में कच्चे माल से किया जाता है, जिसमें बदले में मिश्रित तत्व होते हैं,जबकि खाद्य

पदार्थों का निर्माण आम तौर पर 4 से 5 बुनियादी कच्चे माल से किया जाता है।

(ग) खाद्य पदार्थों के विपरीत, जहां पीएफए अधिनियम और नियमों के माध्यम से विश्लेषण तंत्र उचित रूप से स्थापित किया जाता है, कॉस्मेटिक उत्पादों का उनकी जटिलता के आधार पर विश्लेषण करना कठिन है, जो प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता, बड़ी संख्या में सामग्री आने के कारण कठिन हो जाती है। विभिन्न स्रोत.ऐसी तकनीक उपलब्ध न होने पर लेबल पर प्रतीकों को दर्शाने कीआवश्यकता अव्यावहाँरिक होगी और इससे अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा होगी क्योंकि पशु मूल के अवयवों वाले सौंदर्य प्रसाधनों में शाकाहारी प्रतीक होगा या इसके विपरीत, और इस प्रकार यह मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा जिसके लिए ऐसी आवश्यकता अभिप्रेत है।

(घ) कुछ अपवादों को छोड़कर, आमतौर पर भारत में निर्मित और उपभोग किए जाने वाले खाद्य उत्पादों के विपरीत, कॉस्मेटिक उद्योग आयात और निर्यात दोनों के मामले में अंतरराष्ट्रीय उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और परिणामस्वरूप, उद्योग को बिना किसी तकनीक के इस तरह का लेबल लगाने की आवश्यकता होती है। इस तरह के भेद करने के लिए उपलब्ध होने से न केवल उद्योग पर भारी लागत बढ़ेगी, बल्कि याचिकाकर्ता

सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय कॉस्मेटिक उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी नुकसान होगा। विश्लेषण के लिए किसी भी तकनीक के बिना इस तरह की लेबलिंग को याचिकाकर्ता के सदस्यों के खिलाफ चुनौती दिए जाने की भी संभावना है, जो भारत से निर्यात को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के बजाय भारी लागत और विदेशी मुद्रा की कीमत पर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिए जाएंगे।

8. अपीलकर्ता-एसोसिएशन के अनुसार, उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि कॉस्मेटिक फॉर्मूलेशन दवाओं या खाद्य उत्पादों की तुलना में प्रकृति में जटिल है। अपीलकर्ता-एसोसिएशन ने अपने निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर भरोसा किया:

(1) कॉस्मेटिक फॉर्मूलेशन में 66 खुराक रूप हैं, जैसा कि मानक संदर्भ पुस्तकों में से एक "मैसन डेनावेरी, एल्योर्ड पब्लिशिंग द्वारा द केमिस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स" में सूचीबद्ध है-

(2) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की अनुसूची ऐसे ऐसे 29 प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों को मान्यता देती है।

(3) प्रत्येक प्रकार के फॉर्मूलेशन में CTFA या INCI सामग्री निर्देशिका द्वारा अनुमोदित 12,000 सामग्रियों की विस्तृत पसंद होती है

और कॉस्मेटिक उत्पादों में उपयोग के लिए सुरक्षित होती है। संदर्भ: सीटीएफए ऑनलाइन वेबसाइट।

(4) वास्तव में, कुछ INCI सामग्रियां समान यौगिकों के विभिन्न अनुपातों में अवयवों का मिश्रण हैं। उदाहरण के लिए, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला कार्बोमर ऐक्रेलिक एसिड क्रॉस का एक होमोपोलिमर है जो पेंटाएरीथ्रिटोल के एलिल ईथर, सुक्रोज के एलिल ईथर या प्रोपलीन के एलिल ईथर से जुड़ा होता है। इसमें विभिन्न ग्रेड, 32 व्यापार नाम और 7 व्यापार नाम मिश्रण के आधार पर 7 अलग-अलग तकनीकी नाम हैं।

(5) अधिकतर इत्र कॉस्मेटिक तैयारी का घटक होता है। परफ्यूम अपने आप में मालिकाना फार्मूला है और कई सामग्रियों का मिश्रण है। इत्र का प्रत्येक घटक सिंथेटिक, प्राकृतिक या पशु मूल का हो सकता है। उदाहरण- कस्तूरी इत्र व्यापार रहस्य रचना है। इसमें सिंथेटिक, प्राकृतिक या पशु मूल जैसे किसी भी स्रोत से आने वाली किसी भी संख्या में सामग्री शामिल हो सकती है। आमतौर पर परफ्यूम में 10-100 अलग-अलग सामग्रियां होती हैं।

(6) INCI आवश्यकताओं के अनुसार स्वीकार्य रूप तक पहुंचने के लिए इन सभी सामग्रियों को कई बार शुद्ध किया जाता है। इस स्तर पर

यह शुद्धिकरण का कम से कम चौथा या दसवां चरण है, जिसमें मूल प्रारंभिक सामग्री को पीपीबी स्तर तक भी वापस नहीं पाया जा सकता है। उदाहरण- वनस्पति मूल या विशुद्ध रूप से सिंथेटिक या पशु मूल से फैटी एसिड आधारित सर्फेक्टेंट।

(7) भोजन और औषधि संबंधी फ़ॉर्मूले के मामले में, सीमित सहायक पदार्थों या योजकों की सूची है। औषधि फ़ॉर्मूलों के मामले में, अधिकतर अंश केवल कुछ ही होते हैं और आधिकारिक फार्माकोपिया में मोनोग्राफ प्रकाशित होते हैं। भोजन के मामले में, सूत्र सरल होते हैं और पैक पर घोषित की जाने वाली सामग्री बहुत कम होती है। इसलिए उत्पत्ति को सत्यापित करना बहुत आसान है।

(8) कॉस्मेटिक फ़ॉर्मूले दवा फ़ॉर्मूले से कहीं अधिक जटिल हैं। कॉस्मेटिक फ़ॉर्मूले में संयोजन के गुणकों में उपयोग की जाने वाली हजारों सामग्रियों का स्रोत, उपयोग की गई सामग्रियों की उत्पत्ति की जांच और प्रमाणित करने का कार्य बेहद कठिन बना देता है।

9. यह भी तर्क दिया गया कि उनकी सामग्री सहित लेबलिंग आवश्यकताओं के निर्धारण की शक्ति ड्रग तकनीकी सलाहकार बोर्ड जैसे भारत संघ के अधिकारियों के पास निहित है। ऐसे मामले में उच्च न्यायालय को शाकाहारी या मांसाहारी मूल के आधार पर दवाओं और

सौंदर्य प्रसाधनों के लेबलिंग पर कुछ निश्चित चिह्न प्रदान करने का निर्णय नहीं देना चाहिए था।

10. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि भारत में लगभग 60% आबादी शाकाहारी है, 50% से अधिक निरक्षर है और 90% से अधिक जनता अंग्रेजी नहीं पढ़ सकती है। उत्पादों के अवयवों के खुलासे के लिए जनहित याचिका ऐसे निर्दोष उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए दायर की गई थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे उत्पादों पर यह जानने के लिए आसानी से पहचानने योग्य प्रतीक हो कि क्या उनमें कोई पशु घटक है। उपभोक्ताओं को शाकाहारी सामग्री से बने या प्राप्त उत्पादों और मांसाहारी सामग्री से बने या प्राप्त उत्पादों के बीच सूचित विकल्प चुनने का अधिकार है।

11. इस मामले में निम्न प्रश्न समाहित हैं:

(i) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माताओं को 'मांसाहारी' या 'शाकाहारी' मूल की सामग्री की पहचान करने के लिए अपने पैकेजों में एक विशेष प्रतीक प्रदर्शित करने का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र है; और

(ii) क्या दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के पैकेजों में मांसाहारी सामग्री की उत्पत्ति के बारे में कोई पहचान प्रदर्शित करना व्यावहाँरिक और वांछनीय है।

12. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों पर चर्चा करने से पहले, यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने और कानूनों की एकरूपता लाने की दृष्टि से, खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, 1954 अधिनियमित किया गया। बाद में जब यह महसूस किया गया कि "खाद्य उत्पादों के उपभोक्ता" को पता होना चाहिए कि क्या किसी खाद्य पदार्थ में पक्षी, ताजे पानी या समुद्री जानवर या अंडे या किसी भी पशु मूल के उत्पाद सहित पूरे या किसी भी जानवर का हिस्सा शामिल है, तो भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल, 2001 से खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 2001 को अधिनियमित किया, जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 32 और नियम 42 में संशोधन किया गया और शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य उत्पादों का प्रतीक और रंग कोड पेश किया गया। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के संशोधित नियम 32 के खंड (बी) के तहत, उक्त उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रतीक और रंग कोड द्वारा घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया

था कि क्या खाद्य पदार्थ में कोई मांसाहारी सामग्री है। इंगित करें कि उत्पाद मांसाहारी भोजन है। खाद्य अपमिश्रण निवारण (चौथा संशोधन) नियम, 2001 के नियम 42 के उप-नियम (ZZZ) के खंड (16) को सम्मिलित करके प्रत्येक खाद्य उत्पाद पैकेज पर मांसाहारी भोजन का प्रतीक पेश किया गया था। यह संशोधन 7 मार्च, 2001 से प्रभावी हुआ।

लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि किसी दवा या सौंदर्य प्रसाधन का कोई घटक मांसाहारी मूल का है या नहीं।

13. दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के पैकेज सहित उनके आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करने के लिए "ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940" पेश किया गया था। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 3(बी) में परिभाषित "दवा" इस प्रकार है:

3 (ख) ओषधि के अंतर्गत निम्नलिखित हैं_

(।) मनुष्यों या पशुओं के आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए सब औषधियां और सब पदार्थ जो मनुष्यों या पशुओं में किसी रोग या विकार के निदान, उपचार, शमन या निवारण के लिए या उसमें उपयोग के लिए आशयित हैं, और जिनके अंतर्गत मच्छरों जैसे कीटों के प्रतिकर्षण के

प्रयोजन के लिए मानव शरीर पर लेप की जाने वाली निर्मितियां भी हैं;

(ii) मानव शरीर की संरचना या किसी क्रिया को प्रभावित करने के लिए आशयित या ऐसे ख् पीड़क जन्तु, अथवा कीटों के, जो मनुष्यों या पशुओं में रोग पैदा करते हैं; विनाश के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित (खाद्य से भिन्न) ऐसे पदार्थ जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;,

(iii) सब पदार्थ जो ओषधि के संघटकों के रूप में उपयोग के लिए आशयित हैं, जिनके अंतर्गत खाली जिलेटीन कैपसूल भी हैं; तथा

(iv) ऐसी युक्तियां जो मनुष्यों या पशुओं में रोग या विकार के निदान, उपचार, शमन या निवारण में आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए आशयित हैं, और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं;

'प्रसाधन समग्री' को धारा 3(एएए) में परिभाषित किया गया है :

"3(एएए) "प्रसाधन समग्री" से कोई ऐसी चीज अभिप्रेत है जो साफ करने, सुन्दर बनाने, आकर्षकता बढ़ाने या छवि परिवतिर्त करने के लिए मानव शरीर या उसके किसी भाग में मलने, उडेलने, छिड़कने, फहराने, या समाविष्ट करने या

अन्यथा प्रयुक्त करने के लिए आशयित है तथा प्रसाधन सामग्री के संघटक के रूप में प्रयोग करने के लिए आशयित कोई चीज इसके अंतर्गत है।''

14. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 5 के तहत अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न तकनीकी मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देने और अन्य कार्यों को करने के लिए एक "औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड" का गठन किया जाना है। बोर्ड में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक; भारत के औषधि नियंत्रक; केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के निदेशक; केंद्रीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक; भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के निदेशक, भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष; भारतीय फार्मेसी परिषद के अध्यक्ष; आदि रखे गये।

केंद्र सरकार को धारा 6 के तहत ' दवाओं के नमूनों के विश्लेषण और परीक्षण के लिए' एक निदेशक के नियंत्रण में एक 'केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला' स्थापित करने की भी आवश्यकता है। धारा 7 के तहत, अधिनियम के प्रशासन में पूरे भारत में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी मामले पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और ड्रग्स सलाहकार बोर्ड को सलाह देने के लिए औषधि सलाहकार समिति का गठन किया जाता है।

धारा 8 के अंतर्गत औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के संबंध में

गुणवत्ता के मानक निर्धारित किये गये हैं। अध्याय III 'मिथ्या छाप वाली औषिधियो अपमिश्रित औषधियो, नकल औषधियो मिथ्या छाप वाली प्रसाधन सामग्रिया तथा नकली प्रसाधन सामग्रियो आदि।

धारा 16 के तहत, यह अनिवार्य है कि दवा की गुणवत्ता दूसरी अनुसूची में निर्धारित मानक के अनुरूप होनी चाहिए। इसी प्रकार, किसी कॉस्मेटिक की गुणवत्ता ऐसे मानक के अनुरूप होनी चाहिए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

अधिनियम धारा 18ए के तहत दवा, कॉस्मेटिक के निर्माता और उसके एजेंट के नाम का खुलासा करने से संबंधित है। केंद्र सरकार को धारा 26ए के तहत जनहित में दवा और कॉस्मेटिक के निर्माण आदि पर रोक लगाने का भी अधिकार है। बोतलों, पैकेजों और दवाओं या सौंदर्य प्रसाधनों के अन्य कंटेनरों में पैकिंग में देखी जाने वाली शर्तें, जिसमें धारा 33 के तहत एक नियम बनाकर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पैक की गई दवाओं या सौंदर्य प्रसाधनों के लेबलिंग के तरीके को विनियमित करना शामिल है, जो इस प्रकार है :

"33. नियम बनाने की केंद्रिय सरकार की शक्ति &(1) केंद्रिय सरकार बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात या उसकी सिफारिश पर और शासकिय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अध्याय

के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की यह रॉय हो कि ऐसी परिस्थितयां पैदा हो गई हैं, जिनसे आवश्यक हो गया है कि बोर्ड के साथ ऐसे परामर्श के बना लिए जाएं तो बोर्ड के साथ परामर्श अभिमोचित किया जा सकेगा, किन्तु ऐसी दशा में नियम बना लेने के छह मास के अन्दर बोर्ड से परामर्श किया जाएगा और केंद्रिय सरकार किन्ही भी ऐसे सुझावों पर, जो बोर्ड उक्त नियमों के सशोंधन के सम्बन्ध में दे, विचार करेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यपाकता पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमः-

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

(i) औषधियों 3 (या प्रसाधान सामग्रियों) को बोतलों, पैकजों और अन्य आधानों में पैक करने में 1 (जिनके अंतर्गत पैक करने की ऐसी साम्रगी का उपयोग भी है जो औषधियों के सीधे सम्पर्क में आती है,) पालनीय शर्ते विहित कर सकेंगे और ऐसी शर्तो के उल्लघंन में पैक की गई औषधियों 3 (या प्रसाधान सामग्रियों), का विक्रय विक्रयार्थ, भंडारकरण या प्रदशर्न अथवा वितरण प्रितषिद्ध कर सकेंगेः

(j) पैक की गई औषधियों 3 या प्रसाधन सामग्रियों पर लेबल लगाने का तरीका विनियमित कर सकेंगे, और वे बातें विहित कर सकेंगे जो ऐसेे लेबलों में हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगीः

15. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का भाग XV सौंदर्य प्रसाधनों की लेबलिंग, पैकिंग और मानकों से संबंधित है। नियम 148 के उप-नियम (7) के तहत एक प्रतिशत से अधिक सांद्रता में मौजूद सामग्रियों की सूची को वजन या मात्रा के अवरोही क्रम में सूचीबद्ध करना आवश्यक है।

नियम 149 ए फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से संबंधित एक विशेष प्रावधान है जिसके तहत समाप्ति तिथि के अलावा ट्यूब और कार्टन पर फ्लोराइड की मात्रा का उल्लेख करना अनिवार्य है।

नियम 97 'दवाओं की लेबलिंग' से संबंधित है:

"97. दवाओं की लेबलिंग--- (1) आंतरिक उपयोग के लिए दवा का कंटेनर--

(ए) यदि इसमें अनुसूची जी में निर्दिष्ट कोई पदार्थ शामिल है, तो 'सावधानी: चिकित्सा पर्यवेक्षण के अलावा इस तैयारी को लेना खतरनाक है' शब्दों के साथ लेबल किया जाना चाहिए- स्पष्ट रूप से मुद्रित और एक

पंक्ति से घिरा हुआ है जिसके भीतर कोई अन्य शब्द नहीं होंगे;

(बी) यदि इसमें अनुसूची एच में निर्दिष्ट कोई पदार्थ शामिल है तो इसे प्रतीक औरएक्स के साथ लेबल किया जाना चाहिए और लेबल के बाएं शीर्ष कोने पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और निम्नलिखित शब्दों के साथ भी लेबल किया जाना चाहिए:-

अनुसूची एच दवा-चेतावनी: केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के नुस्खे पर खुदरा बिक्री के लिए;

(सी) यदि इसमें अनुसूची एच में निर्दिष्ट कोई पदार्थ शामिल है, और [स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)] के दायरे में आता है तो उसे एनऔरएक्स प्रतीक के साथ लेबल किया जाएगा जो लाल रंग में होगा और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। लेबल के बाएँ शीर्ष कोने पर, और निम्नलिखित शब्दों के साथ भी लेबल किया जाना चाहिए:-

अनुसूची एच दवा- "चेतावनी:-- केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के नुस्खे पर खुदरा बिक्री के लिए";

(डी) यदि इसमें अनुसूची X में निर्दिष्ट कोई पदार्थ है तो उसे प्रतीक XRX के साथ लेबल किया जाएगा जो लेबल के बाए शीर्ष कोने पर स्पष्ट

रूप से लाल रंग में प्रदर्शित होगा और शब्दो के साथ भी लेबल किया जाएगा।

अनुसूची X दवा- "चेतावनी:-- केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के नुस्खे पर खुदरा बिक्री के लिए";

(2) बाहरी उपयोग के लिए एम्ब्रोकेशन, लिनिमेंट, लोशन, मलहम, एंटीसेप्टिक क्रीम, तरल एंटीसेप्टिक या अन्य तरल दवा के कंटेनर को बड़े अक्षरों में 'केवल बाहरी उपयोग के लिए' शब्द के साथ लेबल किया जाएगा।

(3) केवल किसी जानवर के इलाज के लिए तैयार की गई दवा के कंटेनर पर स्पष्ट रूप से 'मानव उपयोग के लिए नहीं' शब्द का लेबल लगाया जाएगा। केवल पशुओं के इलाज के लिए' और उस पर घरेलू जानवर के सिर को दर्शाने वाला एक प्रतीक होना चाहिए।

(4) मानव रोगों के उपचार के लिए तैयार की गई दवा के कंटेनर पर यदि दवा में औद्योगिक मिथाइलेटेड स्पिरिट है, तो लेबल पर इस तथ्य को इंगित करें और शब्दों के साथ लेबल किया जाए:-

"केवल बाहरी उपयोग के लिए"।

(5) सूची X में निर्दिष्ट पदार्थो को ठोस रूप से वहाँ एक प्रतिष्ठान वाला चिन्ह उप धारा (1) में निर्दिष्ट किये जाने वाले लाल अक्षरों में प्रमुख

रूप से दिया जाएगा

जबकि नियम 105 दवाओं के पैकिंग से सम्बन्धित है जिसमें खुदरा बेचने के लिए निर्धारित साईज जैसे कि सूचि पी में प्रावधान के रूप में शामिल है। अन्य दवाओं के लिए नियम 105 क के तहत और सूचि X के साथ एक अलग पैकिंग निर्धारित की गई है।"

16. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 या उसके तहत बनाए गए नियमों में मांसाहारी या शाकाहारी मूल की सामग्री का उल्लेख या प्रतीक प्रदर्शित करना अनिवार्य नहीं है। निर्माता या अन्य को दवाओं या सौंदर्य प्रसाधनों के लेबल पर 'शाकाहारी' या 'मांसाहारी' का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

केंद्र सरकार को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के तहत औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से 'दवाओं और प्रसाधन सामग्री के लेबल' में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के साथ सार्थक परामर्श के बिना, दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के लेबल को बदलने के लिए कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है या सुझाव नहीं दिया जा सकता है।

17. इससे पहले कुछ व्यक्तियों द्वारा 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स,

1945' में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया था ताकि दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के लेबल पर "शाकाहारी" और "मांसाहारी" शब्दों का उल्लेख किया जा सके। सार्थक विचार-विमर्श के बाद, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने 8 जुलाई, 1999 को आयोजित अपनी 48 वीं बैठक में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जैसा कि नीचे उद्धृत किया गया है:

एजेंडा आइटम नंबर 3 औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव, जिसमें औषधियों/सौंदर्य प्रसाधनों के लेबल पर वी (शाकाहारी) और एनवी (गैर शाकाहारी) शब्दों का उल्लेख आवश्यक होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्री देवदास छोटरॉय, संयुक्त सचिव,मंत्रालय एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और गैर सरकारी संगठन वॉयस के प्रतिनिधि श्री एसआर खन्ना को इस विषय पर बोर्ड के सदस्यों को उनके विचारों से परिचित कराने के लिए नामित किया। श्री छोत्रे ने जानवरों की हत्या के बारे में अपने मंत्रालय की चिंता और उपभोक्ता के सूचना के अधिकार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कुछ उपभोक्ता पशु स्रोत से प्राप्त सामग्री वाले किसी भी उत्पाद के उपयोग से बचना चाहेंगे, यदि उनके पास ऐसी जानकारी का सहारा है और उपभोक्ता की इस आवश्यकता का सम्मान किया जाना आवश्यक है। इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक खाद्य/औषधि उत्पाद पर उसके शाकाहारी या

मांसाहारी पहलुओं के आधार पर वी और एनवी लेबल करने का प्रावधान औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों में लागू किया जा सकता है।

डॉ. एसआर खन्ना ने भी इस तरह की जानकारी के लिए उपभोक्ताओं के अधिकारों पर विस्तार से जोर दिया और वी और एनवी के संदर्भ में दवा के स्रोत को इंगित करने के लिए एक अनिवार्य प्रावधान की इच्छा जताई।

अध्यक्ष ने बताया कि उपभोक्ताओं के सूचना के अधिकार का सम्मान करते हुए वी और एनवी मार्किंग के मुद्दे की चिकित्सा उपचार के व्यापक परिप्रेक्ष्य में जांच की जानी चाहिए, जिसमें कुछ दवाओं जैसे टीके, हार्मोन, बायोटेक उत्पाद आदि का महत्वपूर्ण महत्व है जो जीवन रक्षक प्रकृति के हैं और पशु उत्पत्ति से संबंधित है। (भोजन के विपरीत, दवाएं पसंद से या संतुष्टि के उद्देश्य से नहीं ली जाती हैं)। हालांकि, उन्होंने सुझाव दिया कि शाकाहार की सामान्य समझ के संदर्भ में ऐसी दवाएं जहां जानवरों के ऊतकों का स्थूल भाग जैसे पशु रक्त, यकृत अर्क आदि मौखिक तैयारियों में मौजूद हैं, ऐसी दवाओं के लेबल पर एनवी को चिह्नित करने के लिए बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है।

1. प्रोफेसर जिंदल ने कहा कि दवाओं को उनके स्रोत यानी सिंथेटिक स्रोत, जैव स्रोत और पशु स्रोत को इंगित करने के लिए लेबल किया जा

सकता है। हालाँकि, यह सुझाव व्यावहाँरिक नहीं पाया गया।

2. आईसीएमआर के प्रतिनिधियों प्रो. कोकाटो और श्रीमती मुथुस्वामी ने महसूस किया कि भोजन के मामले में जो उचित हो सकता है वह जरूरी नहीं कि दवाओं के मामले में भी उचित हो जो बीमारी की स्थिति से राहत के लिए और कई बार जीवन को खतरे वाली स्थिति में दी जाती हैं। दवाओं में वी या एनवी अंकित करके शाकाहारी और मांसाहारी की अवधारणा पेश करना उपभोक्ताओं के समग्र हित में नहीं हो सकता है।

3. श्री. प्रफुल्ल सेठ स्पष्ट पशु ऊतकों वाली सीमित संख्या में गैर-महत्वपूर्ण दवाओं जैसे मौखिक टॉनिक आदि के प्रस्ताव पर विचार करने की संभावना के बारे में अध्यक्ष के विचारों से सहमत हुए। उन्होंने यह भी बताया कि वैकल्पिक फॉर्मूलेशन भी उपलब्ध हैं और चिकित्सक इसके बारे में उपभोक्ताओं को सलाह/शिक्षित कर सकते हैं।

4. प्रो. ऐसेडी सेठ, और श्री. और.आनंद राज शेखर ने कहा कि यदि एनवी को चिह्नित करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करना है तो केवल गैर-आवश्यक दवाओं के लिए ही चर्चा की जा सकती है।

5. आईएमए के प्रतिनिधि डॉ. प्रेम अग्रवाल ने दवाओं के क्षेत्र में वी/एनवी की अवधारणा लाने के किसी भी कदम का विरोध किया और यह

भी कहा कि लेबल पर एन.वी.चिह्नित करने के उद्देश्य से दवाओं को आवश्यक या गैर-आवश्यक रूप से वर्गीकृत करना तर्कसंगत नहीं होगा।

6. औषधि नियंत्रक, कर्नाटक, मौखिक रूप से ली जाने वाली और स्पष्ट पशु ऊतकों वाली गैर-आवश्यक दवाओं पर एनवी को चिह्नित करने की सीमा तक सहमत थे, लेकिन दवाओं के क्षेत्र में वी या एनवी बनाने की अवधारणा के पक्ष में नहीं थे।

7. एमसीआई के अध्यक्ष डॉ. केतन देसाई की रॉय थी कि उत्पादों को एनवी के रूप में चिह्नित करना दवाओं के लिए प्रासंगिक नहीं है और उन्हें एक बार आवश्यक और गैर-आवश्यक के रूप में अलग करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव पर खाद्य उत्पादों के लिए विचार किया जा सकता है, दवाओं के लिए नहीं।

8. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियन के प्रतिनिधि डॉ. भार्गव, सीडीऔर लखनऊ के निदेशक डॉ. गुप्ता और श्री एमवी कुमार ने एनवी के साथ दवाओं के उत्पादों को चिह्नित करने की आवश्यकता शुरू करने के खिलाफ मजबूत विचार व्यक्त किए।

9. मेलर पर विस्तार से चर्चा की गई और अन्य सदस्यों ने दवाओं पर एनवी या वी के किसी भी लेबलिंग का समर्थन नहीं किया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एजेंडे में प्रस्तावित दवाओं के "वी/एनवी" या "पशु स्रोत से" लेबलिंग को स्वीकार नहीं किया गया।''

18. संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत एक नागरिक को अभिव्यक्ति और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह अधिकार अनुच्छेद में शामिल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से प्राप्त होता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। [संदर्भ: यूपी राज्य बनाम राज नारॉयण और अन्य, (1975) 4 एससीसी 428; सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार भारत और अन्य बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल और अन्य, (1995) 2 एससीसी 161; पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सीबीआई/ऐसेपीई), (1998) 4 एससीसी 626)]। लेकिन इस तरह के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए बनाए गए कानून के तहत उचित प्रतिबंधों द्वारा सीमित किया जा सकता है।

19. नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के अधिकार की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य के लिए अनिवार्य है। लेकिन ऐसी जानकारी दूसरों के मौलिक अधिकार को प्रभावित किए बिना उस सीमा तक दी जा सकती है, जहां तक यह उपलब्ध और संभव है।

20. वर्तमान मामले में अपीलकर्ता-भारत संघ ने दलील दी थी कि

दवा के अवयवों, विशेष रूप से मांसाहारी मूल के अवयवों से संबंधित जानकारी "आम जनता के हित में" नहीं दी जानी चाहिए। एक विशेष दलील दी गई है कि दवाओं में अंतर करना संभव नहीं है कि ये जीवन रक्षक हैं या अन्यथा।

21. दी गई परिस्थितियों में किसी रोगी की स्थिति ऐसी हो सकती है कि एक दवा जिसे आमतौर पर जीवन रक्षक दवा के रूप में नहीं माना जाता है, वह जीवन बचाने के लिए आवश्यक हो सकती है। ऐसे मामले में जब दवा जीवन रक्षक दवा बन जाती है, तो रोगी या उसके परिचारक के लिए दवा के अवयवों की उत्पत्ति यानी 'शाकाहारी' या 'मांसाहारी' जानना वांछनीय नहीं हो सकता है। यदि जीवन बचाने या किसी बीमारी को खत्म करने के लिए आवश्यक हो तो ऐसा विकल्प रोगी या उसके परिचारक पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

22. यदि किसी दवा या कॉस्मेटिक के अवयवों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी का दावा करना सही है, तो एक शाकाहारी भी अपने भोजन की आदत के आधार पर शाकाहारी घटक की उत्पत्ति के बारे में जानकारी का दावा कर सकता है।

23. भारत में खान-पान की आदत व्यक्ति-व्यक्ति और जगह-जगह के अनुसार अलग-अलग होती है। ऐसी आदत बनाने में धर्म भी अहम भूमिका

निभाता है. जो लोग 'जैन धर्म' का पालन करते हैं वे शाकाहारी हैं लेकिन उनमें से कई लोग जमीन के नीचे उगने वाले कुछ शाकाहारी भोजन जैसे आलू, गाजर, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाते हैं। अधिकांश भारतीय 'शहद' और 'लैक्टोज' (दूध से बनी चीनी) को शाकाहारी मानते हैं लेकिन वैज्ञानिक इन्हें 'मांसाहारी' उत्पाद मानते हैं।

मांसाहारियों में बहुत से लोग 'अशाकाहारी' होते हैं अर्थात् वे जो केवल एक मांसाहारी उत्पाद-अण्डा खाते हैं। वे अन्य मांसाहारी भोजन जैसे जानवर, मछली या पक्षी नहीं खाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंडे को शाकाहारी भोजन मानते हैं। मांसाहारियों में भी, बड़ी संख्या में लोग धार्मिक विश्वास के कारण गोमांस या हैम/पोर्क नहीं खाते हैं। बहुत से मांसाहारी लोग साँप, कीड़े, मेढक या पक्षी नहीं खाते।

व्यक्तिगत मामले में, केंद्र सरकार को 'शाकाहारी' या 'मांसाहारी' घटक की उत्पत्ति निर्दिष्ट करने में कठिनाई महसूस हो सकती है, यदि कोई व्यक्ति उसकी भोजन की आदत का आधार ऐसे 'शाकाहारी' या 'मांसाहारी' घटक की निश्चित उत्पत्ति जानना चाहता है।

24. 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स' में उक्त नियमों में संशोधन के संबंध में ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के किसी भी सुझाव पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इससे पहले

एक संदर्भ में औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड पहले ही रॉय दे चुका है कि दवाओं पर 'शाकाहारी' या 'मांसाहारी' या 'पशु स्रोतों से प्राप्त' का लेबल लगाना वांछनीय नहीं है और इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था।

25. सवाल उठता है कि क्या ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को नियमों में संशोधन करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए परमादेश जारी करना उचित था।

एके रॉय बनाम भारत संघ और अन्य, (1982) 1 एससीसी 271 में, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या न्यायालय को केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के अपना कर्तव्य निभाने के लिए एक परमादेश जारी करना चाहिए और निर्धारित किया:

> "संसद ने 44 वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के समय के संबंध में सवाल को केंद्र सरकार के निर्णय पर छोड़ दिया है, यह अदालत का काम नहीं है कि वह सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर करे, जो कि संसद के निर्णय के अनुसार यह उसके विवेक पर निर्भर करती है कि जब वह ऐसा करना उचित समझे तो वह ऐसा करे। कार्यपालिका

संसद के प्रति उत्तरदायी है और यदि संसद यह समझती है कि कार्यपालिका ने संशोधन के किसी भी प्रावधान को लागू न करके उसके विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, तो वह कार्यपालिका की भर्त्सना कर सकती है,...।"

26. उपरोक्त निर्णय को इस न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य, (1989) 4 एससीसी 187 में देखा और दोहराया, और निर्धारित किया:

"51. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी अदालत विधायिका को कोई विशेष कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। इसी तरह, जब कोई कार्यकारी प्राधिकारी विधायिका के प्रत्यायोजित प्राधिकार के अनुसार अधीनस्थ कानून के माध्यम से विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसे कार्यकारी प्राधिकारी को कानून बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जिसे उसे प्रत्यायोजित विधायी प्राधिकार के तहत करने का अधिकार दिया गया है"।

27. बल राम बाली और अन्य बनाम भारत संघ, (2007) 6 एससीसी 805 में, इस न्यायालय ने गायों, घोड़ों, भैंसों और गिरगिट के वध पर पूर्ण प्रतिबंध के सवाल से निपटने के दौरान शक्तियों के पृथक्करण

पर चर्चा की। इस न्यायालय ने माना कि यह नीति का मामला है जिस पर उचित सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है और न्यायालय किसी विशेष प्रकार का कानून बनाने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल को कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता है। निम्नलिखित टिप्पणी के साथ रिट याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना गया:

> "3. गाय, भैंस और घोड़ों के वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्योंकि यह नीति का मामला है जिस पर निर्णय सरकार को लेना है। इसके अलावा, गाय, भैंस और घोड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध, जैसा कि वर्तमान याचिका में मांग की गई है, केवल उचित विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा ही लगाया जा सकता है। अदालतें किसी विशेष प्रकार का कानून बनाने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल को कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती हैं। इस प्रश्न पर भारत संघ बनाम प्रकाश पी. हिंदुजा और अन्य, (2003) 6 एससीसी 195 में विचार किया गया है, जिसमें रिपोर्ट के पैरा 30 में इसे इस प्रकार रखा गया था:
>
> "30. हमारी संवैधानिक योजना के तहत संसद कानून बनाने

के लिए संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती है और कोई भी बाहरी शक्ति या प्राधिकरण किसी विशेष कानून को लागू करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण एसो. बनाम भारत संघ, (1989) 4 एससीसी 187, में यह माना गया है कि कोई भी अदालत किसी विधायिका को कोई विशेष कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती है। इसी प्रकार, जब कोई कार्यकारी प्राधिकारी विधायिका के प्रत्यायोजित प्राधिकार केअनुसार अधीनस्थ कानून के माध्यम से विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसे कार्यकारी प्राधिकारी को कानून बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जिसे उसे प्रत्यायोजित विधायी प्राधिकार के तहत करने का अधिकार दिया गया है। यह दृष्टिकोण जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम एऔर जक्की, (1992) अनुपूरक 1 एससीसी 548 में दोहराया गया है। एके रॉय बनाम भारत संघ (1982) 1 एससीसी 271 में भी दोहराया गया एवं यह माना गया है कि कोई परमादेश विधायिका द्वारा पारित अधिनियम को लागू करने के लिए जारी नहीं किया जा सकता है।....."

4. उपरोक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर, हमारी रॉय है कि यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दे सकता, जैसा कि रिट याचिका में प्रार्थना की गई थी। तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।"

28. प्रत्यर्थी-रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य, (2002) 5 एससीसी 294 में इस न्यायालय के फैसले को प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि "जहां क्षेत्र खाली रह गया है, वहाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ऐसा निर्देश", यह न्यायालय जारी कर सकता है, लेकिन इस तरह के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि वह क्षेत्र खाली रह गया है क्योंकि ड्रग्स और कॉस्मेटिक नियमों के तहत यह केंद्र सरकार है जिसको ड्रग तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से यह निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है कि संबंधित नियमों में शाकाहारी या मांसाहारी मूल की सामग्री दिखाने या कोई प्रतीक प्रदान करने के लिए कोई संशोधन किया जाना है या नहीं। वास्तव में विचाराधीन मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा विचार-विमर्श किया गया था जब ऐसा मामला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को भेजा गया था, जिसने दिनांक 8 जुलाई, 1999 को अपनी 48 वीं बैठक में इस तरह के सुझाव को

खारिज कर दिया था।

29. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हम मानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास विधानमंडल द्वारा कानून बनाने के लिए सौंपी गई शक्ति के अनुसार अधीनस्थ विधान के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करने के लिए कार्यपालिका को निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। एक विशेष तरीके से, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। इसी कारण से, उच्च न्यायालय किसी भी अंतरिम व्यवस्था का सुझाव देने के लिए भी स्वतंत्र नहीं था, जैसा कि आक्षेपित निर्णय में दिया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई रिट याचिका इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए सुनवाई योग्य नहीं है, उच्च न्यायालय को रिट याचिका को तुरंत खारिज कर देना चाहिए था।

30. परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं और उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश और निर्देश रद्द किये जाते हैं लेकिन खर्चो के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राकेश गोरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।